कपड़ा-उत्पादन

3560. **श्री अजीत जोगी:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1991-92 के दौरान कपड़ा-उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने कपड़ा-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) पिछले अनेक वर्षों से कपड़े का उत्पादन बढ़ रहा है। वर्ष 1991-92 के दौरान यह लगभग उतना ही था जितना कि पिछले वर्ष में था।

(ग) और (घ) सरकार ने कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाए किए हैं। इन में से कुछ उपाय हैं:

(1) नई औद्योगिक नीति में स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्ध को छोड़ करके मिल / विकेन्द्रीकृत विद्युत-करघा स्थापित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(2) वस्त्र मशीनों का आयात किया जा सकता है तथा ऐसी मशीनों पर शुल्क को पहले से कम कर दिया गया है।

(3) वर्ष 1986 में वस्त्र आधुनिकीकरण निधि का सृजन किया गया था तथा अगस्त, 1992 के अन्त तक 397 मामलों में 1367 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 306 आवेदन-पत्रों पर 853 करोड़ रु० की राशि वितरित कर दी गई है।

(4) गिनिंग और प्रोसेसिंग एककों का आधुनिकीकरण।

घाटे में चलने वाली कपड़ा मिलों को अपनी भूमि बेचने की अनुमति

3561. **श्री छोटूभाई पटेल:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रही कपड़ा मिलों के अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपनी भूमि बेचने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलें कौन-कौन सी हैं और किन-किन मिलों ने अब तक अपनी भूमि बेच दी है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० को फालतू भूमि बेचने की अनुमति नहीं है। निजी वस्त्र मिलों के संबंध में अनुमति सम्बद्ध केन्द्रीय और राज्य सरकारों के नियमों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त करनी होती है।

Indo-EEC Textiles agreement

3562. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the European Economic Community pressed for an almost flat rollover of the agreement during the negotiations held recently between India and EEC at Brussels over the Indo-EEC textiles agreement;

(b) if so, what is Government's reaction thereto;

(c) whether Government have achieved any success in negotiating for higher growth rates for all categories under quota and for increased flexibility; and

(d) if so, the final outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Negotiations for renewal of the current Indo-EEC Textile Agreement have not yet been concluded. The Government will continue thier efforts to secure inprovements in the Agreement including higher growth rates and increased flexibilities.

Modernisation of Hosiery Industry

3563. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government propose to take any steps to modernise the Hosiery Industry with a view to catering to the

huge global and domestic markets for knitted goods; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) and (b) Government have taken a number of steps in the recent past to modernise Textile industry including the Hosiery sector which include facilitating import of sophisticated machinery without licensing requirements, import of second-hand machinery without licensing requirements subject to certain conditions, introduction of Export Promotion (Capital Goods) Scheme under which Capital goods could be imported at concessional duty of 15% and 25% subject to appropriate export obligation etc.

Non-payment of dues to the cotton cooperatives

3564. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of cotton cooperatives had supplied cotton to the N.T.C. Mills;

(b) whether it is also a fact N.T.C. has not yet paid dues to these cotton cooperatives; and

(c) if so, by when these dues are likely to be cleared by the N.T.C?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Yes, Sir.

(b) Some of the dues have not been cleared.

(c) Since cotton is purchased by NTC mills on credit terms, at any given point of time there are bound to be certain outstanding for payment. It is expected that as adequate are received by NTC, as part of the Turn Around strategy, NTC Mills would be able to clear most of its dues.

पाकिस्तान से कपास का आयात

3565. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक गणमान्य नेताओं और किसान संगठनों ने सरकार का ध्यान मार्च-अप्रैल, 1992 के दौरान पाकिस्तान से कपास की लगभग तीन लाख गांठ आयात करने की ओर दिलाया है और पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय कपास निगम द्वारा पंजाब, हरियाणा और गंगानगर (राजस्थान) से बड़े पैमाने पर उचित मूल्य पर कपास की खरीद किए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां।

(ख) हथकरघा क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अप्रैल, 1992 में कताई मिलों में आयात शुल्क के बिना कपास की 2 लाख गाठों के आयात की अनुमति दी थी। तथापि कपास की घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत परिस्थिति के कारण कोई आयात नहीं हो सका। फिर भी कपास के आयात की अनुमति मौजूदा आयात-निर्यात नीति के अनुसार सूती यार्न / फैब्रिक और मेड अप्स के निर्यात के आधार पर अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत दी जाती है। सी सी आई भी मौजूदा बाजार दर पर पंजाब, हरियाणा और गंगानगर (राजस्थान) के बराबर की खरीददारी करता है।

Purchase of Jute in Assam

3566. SHRI MATANG SING: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that jute growers of Assam could not sell their jute produce this year through the Agents of JCI as JCI did not purchase jute from the growers at different sale centres in the State.

(b) the amount allocated to the JCI for purchasing jute in different sale centres in the State like Kharupetia in Darrang district, Dhing in Nagon district, Gauripur in Dhubri district and Barpcta in Barpcta district this year;